

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)( )नियम/डी.एल.बी./17/ 21167-21200 जयपुर, दिनांक: 14/6/17  
जिला कलेक्टर,  
समस्त राजस्थान।

विषय: राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 121 के अन्तर्गत कराधान से संबंधित अपील पत्रावलियां हस्तान्तरण करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 121 कराधान से संबंधित अपील का प्रावधान राजस्थान नगर पालिका (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित कर दिया गया है। जिसका राजस्थान राज-पत्र भाग-(iv)-क में दिनांक 18.05.2017 को प्रकाशित हो गया है जो निम्नवत् है:-

"121. कराधान से संबंधित अपीले— कर-निर्धारण या कर-निर्धारण में किसी परिवर्तन के विरुद्ध अपील, और ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें यथापूर्वोक्त कोई अपील नहीं की गयी है, धारा 130 के अधीन मांग के किसी नोटिस के विरुद्ध अपील,—

- (क) नगर निगम के मामले में, आयुक्त को; और  
(ख) नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड के मामले में,  
संबंधित स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उप निदेशक को,  
की जा सकेगी"।"

अतएव उपरोक्त संशोधित प्रावधानानुसार कराधान से संबंधित समस्त लम्बित अपीले संबंधित अपील अधिकारी को हस्तान्तरित करावे।

संलग्न: राजस्थान राज-पत्र भाग-(iv)-क

दिनांक 18.05.2017

  
(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.8(ग)( )नियम/डी.एल.बी./17/ 21201-21590 जयपुर, दिनांक: 14/6/17  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, मा.मंत्रीमहोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
- समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
- महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राज0।
- समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
- आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगरनिगम/परिषद/पालिका समस्त राज0।
- सुरक्षित पत्रावली।

  
(अशोक कुमार सिंह)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज—पत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

*Published by Authority*

वैशाख 28, गुरुवार, शाके 1939—मई 18, 2017  
*Vaisakha 28, Thursday, Saka 1939-May 18, 2017*

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 18, 2017

संख्या प. 2 (24) विधि/2/2017:- राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मई, 2016 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2017  
(2017 का अधिनियम संख्यांक 27)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मई, 2017 को प्राप्त हुई]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अइसठवं वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 45 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 45 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (द) और (ध) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"121. कराधान से संबंधित अपीलें.- कर-निर्धारण या कर-निर्धारण में किसी परिवर्तन के विरुद्ध अपील, और ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें यथापूर्वकत कोई अपील नहीं की गयी है, धारा 130 के अधीन मांग के किसी नोटिस के विरुद्ध अपील,-  
 (क) नगर निगम के मामले में, आयुक्त को; और  
 (ख) नगर परिषद् और नगरपालिक बोर्ड के मामले में,  
 संबंधित स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उप निदेशक को,  
 की जा सकेगी।"

मनोज कुमार व्यास,  
 प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
 (GROUP-II)  
 NOTIFICATION**

**Jaipur, May 18, 2017**

No. F. 2 (24) Vidhi/2/2017.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of (the Rajasthan Nagarpalika Chaturtha Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (2017 ka Adhiniyam Shankhyank 27) :-

**(Authorised English Translation)**

**THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (FOURTH  
 AMENDMENT) ACT, 2017**

**(Act No. 27 of 2017)**

[Received the assent of the Governor on the 17<sup>th</sup> day of May, 2017]

*An*

*Act*

*further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-